नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 124
दि. 06.02.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# सहकार से स्टीयरिंग तक: 'भारत टैक्सी' के साथ बदली देश की कैब यात्रा

नई दिल्ली। देश के परिवहन और शहरी मोबिलिटी परिदृश्य में गुरुवार का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'भारत टैक्सी' ऐप सेवा को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। यह केवल एक नई कैब बुकिंग सुविधा नहीं है, बल्कि भारत के कैब सेक्टर में वर्षों से चली आ रही कमीशन-आधारित और सर्ज प्राइसिंग वाली व्यवस्था के विकल्प के तौर पर सामने आई एक नई सोच है। सहकारी मॉडल पर आधारित यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को केंद्र में रखता है, जहां वे केवल सेवा देने वाले नहीं, बल्कि व्यवस्था के भागीदार और मालिक हैं। सरकार का दावा है कि यह पहल टैक्सी ड्राइवरों की आय, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा—तीनों को एक साथ मजबूत करेगी, जबकि यात्रियों को पारदर्शी और स्थिर किराया उपलब्ध कराएगी। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारिता की भावना को अब परिवहन जैसे आधुनिक और तकनीक-आधारित क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज लगभग आठ लाख सारथी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सहकारी टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है और यह आने वाले दो वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक पूरे देश में फैल जाएगी। उनका कहना था कि निजी कैब कंपनियों के मॉडल में ड्राइवरों को अक्सर भारी कमीशन और मनमाने किराये की मार झेलनी पड़ती है, जबकि 'भारत टैक्सी' उन्हें जीरो कमीशन और नो सर्ज प्राइसिंग का भरोसा देती है। इससे ड्राइवरों की रोज़मर्रा की कमाई सीधे उनके हाथ में जाएगी और यात्रियों को पीक आवर्स में अतिरिक्त शुल्क देने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। दो महीने तक चले पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस सेवा को फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में शुरू किया गया है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, पायलट चरण में इस प्लेटफॉर्म को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली, उसने इसके राष्ट्रीय विस्तार का रास्ता साफ कर दिया। इस दौरान तीन लाख से अधिक ड्राइवर 'भारत टैक्सी' से जुड़े और एक लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऐप पर पंजीकरण कराया। दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में प्रतिदिन दस हजार से अधिक राइड पूरी की गईं और अब तक ड्राइवरों को सीधे लगभग दस करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि सहकारी मॉडल केवल सैद्धांतिक विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक और टिकाऊ

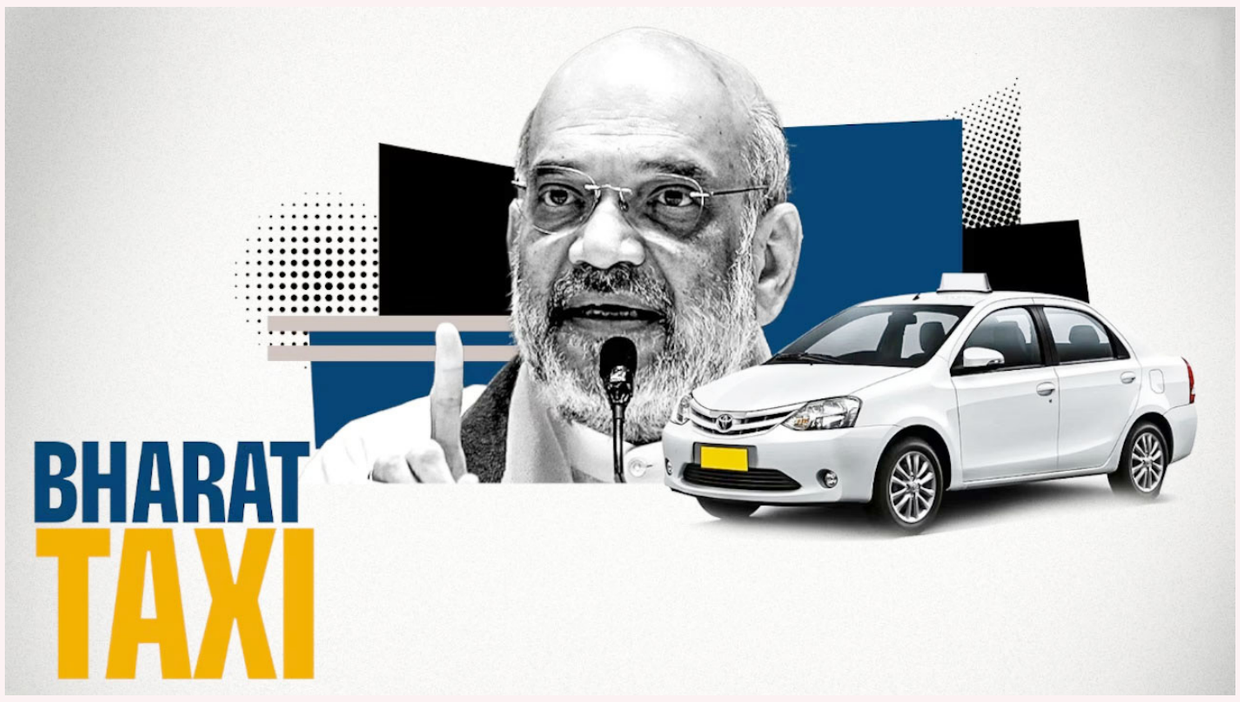


विकल्प बन सकता है।

'भारत टैक्सी' की सबसे बड़ी विशेषता इसका ड्राइवर-स्वामित्व वाला ढांचा है। इस प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा किसी कॉर्पोरेट इकाई तक सीमित न रहकर सीधे ड्राइवरों के बीच वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और रिटायरमेंट बचत जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले टैक्सी चालकों के लिए लंबे समय से एक बड़ी जरूरत रही है। इसके अलावा ड्राइवरों पर किसी तरह की एक्सक्लूसिविटी शर्त नहीं होगी, यानी वे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इससे उनके पास आय के अधिक विकल्प होंगे और वे किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहेंगे।

महिला सशक्तिकरण को भी इस पहल का अहम हिस्सा बनाया गया है। अमित शाह ने बताया कि 'भारत टैक्सी' प्लेटफॉर्म पर 'बाइक दीदी' सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत महिलाएं बाइक टैक्सी चलाकर अपनी आजीविका कमा सकेंगी। अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर इस पहल से जुड़ चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में उनकी संख्या तेजी से बढ़े। यह कदम न केवल महिलाओं को रोजगार देगा, बल्कि शहरी परिवहन में उनकी भागीदारी को भी मजबूत करेगा।

सरकार की योजना अगले दो वर्षों में देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में 'भारत टैक्सी' का विस्तार करने की है। हर राज्य में समर्पित सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां ड्राइवरों को तकनीकी, प्रशासनिक और संचालन से जुड़ी मदद मिलेगी। दिल्ली में फिलहाल सात ऐसे सहायता केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म को नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गहराई से जोड़ा जाएगा, ताकि भुगतान, पहचान सत्यापन और डेटा सुरक्षा जैसे पहलुओं में पारदर्शिता और भरोसा बना रहे। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि 'भारत टैक्सी' का सहकारी मॉडल भारतीय कैब सेक्टर में संतुलन ला सकता है। जहां एक ओर निजी कंपनियों ने तकनीक और सुविधा के स्तर पर बड़ा बदलाव किया, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों की आय और अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में 'भारत टैक्सी' एक ऐसा विकल्प पेश करती है, जिसमें तकनीक, सहकार और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ा गया है। यात्रियों के लिए यह सेवा स्थिर किराये, पारदर्शी भुगतान और भरोसेमंद ड्राइवर नेटवर्क का वादा करती है, जबकि ड्राइवरों के लिए यह सम्मानजनक आय और भविष्य की सुरक्षा का माध्यम बन सकती है। लॉन्च के मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह पहल केवल कैब सेवा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में एक व्यापक मोबिलिटी इकोसिस्टम का रूप लेगी, जो टिकाऊ, समावेशी और सहकारिता आधारित होगा। उनका कहना था कि जब ड्राइवर मालिक बनेंगे, तब व्यवस्था अपने आप अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित हो जाएगी। 'भारत टैक्सी' इसी सोच का परिणाम है, जहां सड़क पर दौड़ती हर टैक्सी केवल सवारी नहीं ढोएगी, बल्कि सहकार, आत्मनिर्भरता और साझेदारी की नई कहानी भी लिखेगी।

# सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अनुराग ठाकुर पर बीसीसीआई से जुड़ा प्रतिबंध समाप्त, क्रिकेट प्रशासन में वापसी का रास्ता साफ

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई की गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर वर्ष 2017 से लगे प्रतिबंध को हटाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह रोक आजीवन नहीं मानी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि लंबे समय तक चले इस प्रतिबंध को जारी रखना न्यायसंगत और अनुपातिक नहीं होगा। इस आदेश के बाद अनुराग ठाकुर अब क्रिकेट प्रशासन से जुड़े किसी भी पद या भूमिका के लिए तकनीकी रूप से पात्र हो गए हैं।

यह मामला करीब नौ वर्ष पुराने उस विवाद से जुड़ा है, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था। वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू कराने के दौरान कड़ा रुख अपनाया था। उस समय बीसीसीआई पर सुधारों को लागू करने में टालमटोल और अदालती आदेशों की अवहेलना के आरोप लगे थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर तत्कालीन

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया गया था। साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया था कि दोनों अधिकारी बीसीसीआई के किसी भी कार्य या गतिविधि से खुद को अलग रखेंगे।

बीते वर्षों में इस आदेश को लेकर यह धारणा बन गई थी कि यह प्रतिबंध स्थायी या आजीवन है, जिसके चलते अनुराग ठाकुर की क्रिकेट प्रशासन में वापसी पूरी तरह बंद मानी जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 2017 के आदेश के उस विशेष हिस्से को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें बीसीसीआई से दूर रखा गया था। उनकी ओर से दलील दी गई कि अदालत के आदेश का उद्देश्य सुधारों को लागू कराना था, न कि किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए दंडित करना।

मामले की सुनवाई के दौरान वर्तमान पीठ ने 2017 के आदेश की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि उस समय दिया गया निर्देश किसी भी तरह से 'लाइफ बैन' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को लगभग नौ वर्षों तक खेल प्रशासन से दूर रखना अपने आप में एक गंभीर दंड है और इसके बाद भी प्रतिबंध को जारी रखना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। पीठ ने यह भी माना कि जिस उद्देश्य के लिए यह कार्रवाई की गई थी, वह समय के साथ पूरा हो चुका है और अब उसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी भी की कि किसी भी दंड या प्रतिबंध को उसके उद्देश्य और अवधि के अनुपात में होना चाहिए। इतने लंबे समय तक प्रतिबंध को जारी रखना 'अनुपातहीन' होगा और इससे न तो संस्थागत सुधारों को कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा और न ही न्याय की भावना पूरी होगी। इसी आधार पर अदालत ने 2017 के उस निर्देश को वापस ले लिया, जिसके चलते अनुराग ठाकुर बीसीसीआई से पूरी तरह बाहर थे।

इस फैसले को भारतीय क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लंबे और जटिल विवादों में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। वर्षों से चले आ रहे इस प्रकरण के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अनुराग ठाकुर के लिए क्रिकेट से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के दरवाजे दोबारा खुल गए हैं। हालांकि, वे भविष्य में किसी पद पर आएंगे या नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन कानूनी अड़चन अब समाप्त हो चुकी है।

शीर्ष अदालत के इस निर्णय को व्यापक रूप से यह संदेश देने वाला भी माना जा रहा है कि सुधारों के नाम पर लगाए गए प्रतिबंध अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकते। न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि दंड का उद्देश्य सुधार और अनुशासन होता है, न कि स्थायी बहिष्कार। अनुराग ठाकुर को मिली यह राहत न केवल उनके लिए, बल्कि खेल प्रशासन से जुड़े अन्य मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत के रूप में देखी जा रही है।

# पुलिस नेतृत्व में मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक: 'कार्यवाहक' डीजीपी व्यवस्था को बताया कानून और संविधान की भावना के खिलाफ

नई दिल्ली। देश में पुलिस व्यवस्था के शीर्ष पद पर लंबे समय से चली आ रही 'कार्यवाहक' पुलिस महानिदेशक की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब इस तरह की प्रशासनिक चालाकी और टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमित डीजीपी की नियुक्ति में जानबूझकर देरी करना न केवल योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह पुलिस सुधारों को लेकर दिए गए ऐतिहासिक निर्देशों की आत्मा के भी खिलाफ है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था ने पुलिस प्रशासन को अस्थिर और राजनीतिक दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि 'प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार' मामले में पुलिस सुधारों के लिए जो दिशानिर्देश तय किए गए थे, उनका उद्देश्य पुलिस को पेशेवर, स्वतंत्र और जवाबदेह बनाना था। नियमित डीजीपी की नियुक्ति इसी व्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि इससे नीतिगत निरंतरता, प्रशासनिक स्थिरता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित

होती है। इसके बावजूद कई राज्य सरकारें वर्षों तक नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं करतीं और कार्यवाहक अधिकारियों के सहारे काम चलाती रहती हैं, जिससे पुलिस तंत्र में असमंजस और असंतोष की स्थिति पैदा होती है।

अदालत ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए संघ लोक सेवा आयोग को राज्यों पर निगरानी की अहम भूमिका सौंपी है। अब यूपीएससी केवल नामों का इंतजार करने वाली संस्था नहीं रहेगी, बल्कि उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को समय रहते डीजीपी चयन के प्रस्ताव भेजने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिख सके। यदि इसके बावजूद कोई राज्य सरकार आयोग के निर्देशों की अनदेखी करती है या जानबूझकर प्रक्रिया में देरी करती है, तो यूपीएससी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कदम राज्यों की प्रशासनिक शिथिलता पर अंकुश लगाने और चयन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान नियमों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है। राज्य सरकारों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजने होते हैं, जिसके बाद आयोग योग्यता, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करता है। राज्य सरकार को इसी पैनल में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करना होता है। लेकिन व्यवहार में कई राज्य इस प्रक्रिया से बचने के लिए नाम ही नहीं भेजते, ताकि मनचाहे अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी बनाकर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। अदालत ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन और संस्थागत व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करार दिया।

इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि तेलंगाना से जुड़े एक मामले से सामने आई, जिसने देशभर की स्थिति को उजागर कर दिया। यूपीएससी ने अदालत को बताया कि तेलंगाना में अंतिम नियमित डीजीपी अनुराग शर्मा वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्षों तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा और पुलिस का शीर्ष पद कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चलता रहा। लगभग आठ साल की लंबी देरी के बाद अप्रैल 2025 में जब नाम भेजे गए, तो आयोग ने इसे प्रक्रियात्मक उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसी घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल तेलंगाना, बल्कि सभी राज्यों के लिए स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए।

अदालत ने यह भी कहा कि कार्यवाहक डीजीपी की लंबी अवधि तक नियुक्ति से पुलिस बल के भीतर अनुशासन, मनोबल और नेतृत्व की स्पष्टता प्रभावित होती है। वरिष्ठ अधिकारी, जो नियमों के अनुसार इस पद के हकदार होते हैं, खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, जबकि कार्यवाहक पद पर बैठे अधिकारी अस्थायी होने के कारण स्वतंत्र निर्णय लेने में झिझकते हैं। इसका सीधा असर कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यक्षमता पर पड़ता है।

# आसमान की सुरक्षा पर संसद की नजर: एक साल में 377 विमानों में बार बार तकनीकी गड़बड़ी, रखरखाव और निगरानी पर उठा बड़ा सवाल

नई दिल्ली। संसद के चालू सत्र में भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और रखरखाव से जुड़ा एक अहम मुद्दा सामने आया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी ने यह स्पष्ट किया है कि देश के नागरिक विमानन तंत्र में बीते एक वर्ष के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर लगातार निगरानी और विश्लेषण किया गया है। सरकार ने सदन को अवगत कराया कि जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2026 के बीच विभिन्न एयरलाइंस के कुल 377 विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां पाई गईं। इन विमानों की पहचान केवल शिकायतों के आधार पर नहीं, बल्कि विस्तृत डेटा विश्लेषण, सुरक्षा ऑडिट और उड़ान संचालन से जुड़ी रिपोर्टों के अध्ययन के बाद की गई है। यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार के दौर से गुजर रहा है।

मंत्री ने बताया कि बार-बार तकनीकी गड़बड़ी का अर्थ यह नहीं है कि ये विमान उड़ान के लिए असुरक्षित थे, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि इन विमानों में निर्धारित अवधि के भीतर समान या मिलती-जुलती तकनीकी समस्याएं दोहराई गईं, जिन पर विशेष निगरानी की आवश्यकता पड़ी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसे विमानों को चिन्हित कर उनके रखरखाव रिकॉर्ड, इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं और परिचालन मानकों की गहन समीक्षा की। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी संभावित जोखिम को पहले ही रोकने के उद्देश्य से अपनाई गई है।

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार,

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के 405 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 148 विमानों में बार-बार तकनीकी गड़बड़ी दर्ज की गई। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इंडिगो का विमान बेड़ा देश में सबसे बड़ा है और इसकी उड़ानों की संख्या भी अन्य एयरलाइंस की तुलना में अधिक है। इसी तरह, एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 विमानों में तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 विमानों में बार-बार तकनीकी खामियां सामने आईं। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि बड़े बेड़े वाली एयरलाइंस के लिए विमानों का नियमित और उच्च गुणवत्ता वाला रखरखाव एक बड़ी परिचालन चुनौती बना हुआ है, खासकर ऐसे समय में जब उड़ानों की संख्या और अंतरराष्ट्रीय मार्गों का विस्तार तेजी से हो रहा है।

अन्य एयरलाइंस की स्थिति पर भी सरकार ने सदन को जानकारी दी। स्पाइसजेट के 43 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 16 विमानों में बार-बार तकनीकी गड़बड़ी पाई गई। वहीं अपेक्षाकृत नई एयरलाइन अकासा एयर के 32 विमानों में से 14 विमानों में तकनीकी खामियां दर्ज की गईं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नई या पुरानी, बड़ी या छोटी—सभी एयरलाइंस के लिए समान सुरक्षा मानक लागू होते हैं और किसी भी कंपनी को नियमों में छूट नहीं दी जाती। जिन विमानों में बार-बार गड़बड़ी पाई जाती है, उनके लिए अतिरिक्त जांच, रखरखाव निर्देश और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी रूप से संचालन से हटाने जैसे कदम भी उठाए जाते हैं।

हालांकि, इन आंकड़ों के बीच एक राहत देने वाला पहलू भी सामने आया है। मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में उड़ानों के दौरान होने वाली तकनीकी गड़बड़ी की कुल घटनाओं में लगातार कमी आई है। वर्ष 2023 में जहां ऐसी 448 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 421 रह गई। वर्ष 2025 में यह आंकड़ा और कम होकर 353 तक आ गया। सरकार का कहना है कि यह गिरावट इस बात का संकेत है कि विमानन सुरक्षा और रखरखाव के क्षेत्र में उठाए गए कदम धीरे-धीरे असर दिखा रहे हैं। बेहतर प्रशिक्षण, उन्नत निगरानी प्रणाली और सख्त अनुपालन प्रक्रिया के कारण तकनीकी घटनाओं की आवृत्ति में कमी दर्ज की जा रही है।

नागर विमानन महानिदेशालय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि डीजीसीए एक मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा निगरानी तंत्र के तहत काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में डीजीसीए द्वारा कुल 3,890 निगरानी निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें नियमित ऑडिट, अचानक जांच और विशेष सुरक्षा निरीक्षण शामिल हैं। इन निरीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी एयरलाइंस, विमान रखरखाव संगठन और हवाई अड्डा संचालक नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

सरकार का यह भी कहना है कि विमानन क्षेत्र में तकनीकी गड़बड़ियों को केवल संख्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके कारणों और समाधान पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई बार मौसम की स्थिति, संचालन की तीव्रता, विमानों की उम्र और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे भी रखरखाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मंत्रालय और डीजीसीए का प्रयास है कि एयरलाइंस के साथ मिलकर दीर्घकालिक समाधान तैयार किए जाएं, ताकि तकनीकी विश्वसनीयता और यात्रियों का भरोसा दोनों मजबूत हो सकें।

संसद में यह मुद्दा उठने के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक विमर्श भी तेज होने की संभावना है। हवाई यात्रा को देश में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन माध्यमों में गिना जाता है, और सरकार का दावा है कि वह इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी विमान को केवल व्यावसायिक दबाव के कारण उड़ान की अनुमति नहीं दी जाती। तकनीकी मानकों, अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाता है।


नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

## संपादकीय

# डराते हैं गाजियाबाद-कुल्लू के आत्मघात

ऑनलाइन गेमिंग के भ्रमजाल में फंसकर, उसे हकीकत मानकर जीने वाले किशोरवय जरा से विचलन से आत्मघात की राह पकड़ना अंतिम समाधान समझ लेते हैं। धीरे-धीरे किशोरवय को अपने चपेट में लेने वाली यह प्रवृत्ति कितनी घातक हो सकती है, उसका उदाहरण बुधवार को घटी दो भयावह घटनाएं हैं। एक हृदयविदारक घटना में गाजियाबाद की तीन अल्पवयस्क बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन कोरियन गेम की दीवानी बहनें कोरिया में जाकर बसने और वहीं नया जीवन शुरू करने का सपना देखती थीं। घर वालों ने जब उनकी ऑनलाइन सनक से परेशान होकर उनसे मोबाइल छीन लिए, तो वे तनाव व अवसाद में घिर गई। फिर तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी घटी जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम के अपने एक विदेशी साथी के बिछुड़ने के गम में घर में आत्महत्या कर ली। किशोर दसवीं का छात्र था। इन घटनाओं ने आम जनमानस को झकझोर कर रख दिया और बच्चों को लेकर फिक्र बढ़ा दी। निस्संदेह, ये आत्मघात की घटनाएं, ऑनलाइन गतिविधियों के अतिरेक से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को लेकर गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की तीन सुकोमल बहनें असमय काल-कवलित हो गईं। पुलिस भी प्रथम दृष्टया मान रही है कि इस दुखद घटना के पीछे ऑनलाइन गेमिंग ऐप का अत्यधिक उपयोग और घर में इसके इस्तेमाल को लेकर हुआ विवाद था। वहीं दूसरी ओर जांच अधिकारी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पारिवारिक परिस्थितियों और मनोवैज्ञानिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इसी तरह कल्लू की घटना भी विचलित करने वाली है। जहां विदेश में रहने वाले एक ऑनलाइन गेमिंग मित्र के साथ संपर्क टूट जाने के बाद अत्याधिक मानसिक व्याकुलता से ग्रस्त पंद्रह वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निश्चित रूप से आत्मघात की ये घटनाएं हमारे नीति-नियंताओं और अभिभावकों को आसन्न संकट के प्रति सचेत करती हैं। दरअसल,ये दुखद घटनाएं एक घातक प्रवृत्ति को ही उजागर करती हैं कि गेमिंग और डिजिटल संपर्क लाखों युवाओं को आभासी समुदाय और मनोरंजन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भावनात्मक कमजोरियों,सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति न होने जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। हालांकि, वहीं दूसरी ओर समाज विज्ञानी इस बात पर भी बल देते हैं कि केवल गेमिंग या ऑनलाइन मित्रता ही आत्महत्या का कारण नहीं बन सकती हैं। निस्संदेह, आत्महत्या एक जटिल और बहुआयामी घटना है। लेकिन समस्याग्रस्त डिजिटल जुड़ाव, विशेष रूप से जब यह ऑफलाइन जीवन से अलगाव, बाधित शिक्षा और तीव्र भावनात्मक तनाव के साथ होता है तो संवेदनशील युवा मन में परेशानी को और बढ़ा सकता है। निस्संदेह, इन दुखद घटनाओं के सामने आने के बाद डिजिटल युग में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इन त्रासदियों को टालने हेतु तात्कालिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिये जरूरी है कि माता-पिता को भी डिजिटल जागरूकता प्रदान की जाए। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने तथा किशोरों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की जरूरत है। वक्त की दरकार है कि परिवारों के भीतर खुले संवाद को बढ़ावा दिया जाए। जिससे बच्चे किसी संकट में फंसने से पहले अपनी बात अपने परिवार से कह सकें। गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे बच्चों को संवेदनशील ढंग से सुना जाना चाहिए। नीति-नियंताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन वातावरण नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे। आस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विकसित देशों ने किशोरवय को कथित सोशल मीडिया के संजाल से बचाने के लिये एक उम्र तक उनके सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है। दरअसल, सोशल मीडिया व अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्मों पर इतनी घातक व भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं कि वे बच्चों के सुकोमल मस्तिष्क पर घातक असर डाल सकती हैं।

# आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत?

> देखा जाए तो भारत का विदेश व्यापार वर्तमान में भारी घाटे में है, जो दिसंबर 2025 में 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विपरीत स्थिति यानी कारोबारी घाटा चीन, रूस, यूएई और इराक जैसे 75 देशों के साथ है जहां व्यापार घाटा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां से आयात निर्यात से बहुत ज्यादा होता है।

भारत की सियासत 'वैचारिक अकाल' से पीड़ित है, जिसका असर हमारे घरेलू कारोबार के अलावा विदेश व्यापार पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। सच कहूं तो राष्ट्र की 'आर्थिक स्वायत्तता' ही चीन और रूस जैसे देशों के समक्ष गिरवी प्रतीत हो रही है। यह ठीक है कि रूस हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मददगार मित्र है, जिसके द्वारा शोषण किया जाना स्वाभाविक है। लेकिन चीन जैसे मजबूत और पड़ोसी शत्रु देश को इतना भारी कारोबारी लाभ देने के बावजूद यदि हम उसे अपना मित्र नहीं बना पाए तो यह बात सिर्फ यही चुगली करती है कि हमारी आंतरिक दलित और पिछड़ी नीतियों की वजह से भारत रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछड़ता प्रतीत होता हैं। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ यह सवाल दाग रहे हैं कि आखिर घाटे वाले विदेश व्यापार को मुनाफे वाले अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कब और कैसे बदलेगा भारत? देखा जाए तो भारत का विदेश व्यापार वर्तमान में भारी घाटे में है, जो दिसंबर 2025 में 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया। विपरीत स्थिति यानी कारोबारी घाटा चीन, रूस, यूएई और इराक जैसे 75 देशों के साथ है जहां व्यापार घाटा हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहां से आयात निर्यात से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमारा सरकारी प्रयास निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित हैं, लेकिन अधिशेष (सर्विस ट्रेड को छोड़कर गुड्स ट्रेड में) प्राप्त करने का कोई निश्चित समयसीमा नहीं है। वर्तमान स्थिति में भारत का व्यापार घाटा एफवाई (FY) 2026 के पहले क्वार्टर में एफटीए (FTA) देशों के साथ 59% बढ़कर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया, जहां निर्यात 9% गिरा और आयात 10% बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में



यह 25.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अनुमान 2027 तक -32 अरब डॉलर का है। यानी वर्तमान के साथ साथ निकट भविष्य भी अंधकारमय है।

खासकर रूस, चीन और आसियान जैसे साझेदारों के साथ ही घाटा प्रमुख समस्या बनी हुई है। रूस तो भारत का भरोसेमंद मित्र है, हथियार व तकनीकी आपूर्तिकर्ता है। लेकिन चीन के खिलाफ आसियान देश समूह को संतुलित करने/रखने की नीति हम पर अब भारी महसूस हो रही है। लुक ईस्ट की नीति भी सफेद हाथी साबित हुई। हां, लाभ देने वाले पश्चिमी देशों को यदि विकल्प दिखाकर काबू में रखना है तो फिर कुछ नहीं कहना। क्योंकि यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होते ही अमेरिकी अकड़ ढीली पड़ गई और उसके साथ भी एफटीए हो गया।

हालांकि भारत की कारोबारी चुनौतियाँ यह हैं कि चीन, रूस और कोरिया के अलावा स्विट्जरलैंड, यूएई, इराक जैसे देशों से आयात अधिक है, जबकि अमेरिकी कूटनीतिक व रणनीतिक टैरिफ ने निर्यात प्रभावित किया, जबकि अब इसका खतरा टल गया है क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एफटीए (FTA) के बावजूद आसियान निर्यात गिरा, और सोना-तेल आयात घाटा बढ़ा रहा। मसलन, लॉजिस्टिक्स, अनुपालन लागत और वैश्विक टैरिफ हमारे विदेश व्यापार की प्रमुख बाधाएँ हैं। फिर भी भविष्य की संभावनाएँ बरकरार हैं। खासकर घाटा कम करने के लिए निर्यात विविधीकरण, जीवीसी (GVC) एकीकरण और अवसंरचना सुधार आवश्यक हैं, लेकिन पूर्वानुमान 2027 तक भी घाटा दिखाते हैं।

कहना न होगा कि भारत का विदेश व्यापार घाटा मुख्य रूप से चीन, रूस, स्विट्जरलैंड, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ है। दरअसल, यह घाटा ऊर्जा आयात, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल की उच्च निर्भरता के कारण बढ़ रहा है। इसलिए भारत को नीतिगत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन घाटों पर काबू पाना होगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से अधिकांश (शीर्ष 10 में 9) के साथ हमारा घाटा वाला कारोबार हैः-

पहला, चीनः सबसे बड़ा घाटा (2024-25 में $99.2 बिलियन, 2025 में $116 बिलियन तक), वजह- इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, APIs और केमिकल्स आयात से।

दूसरा, रूसः $57 बिलियन (2023-24), वजह- मुख्यतः कच्चा तेल आयात से।

तीसरा, यूएईः $9.47 बिलियन, वजह- तेल और सोना आयात।

चतुर्थ, स्विट्जरलैंडः वजह- सोना और घड़ियां आयात से।

पांचवां, इराकः वजह- कच्चा तेल।

छठा- सऊदी अरबः वजह- कच्चा तेल।

बताया जाता है कि उपर्युक्त देशों से घाटे के कारण रणनीतिक तैयारियों में कमियां और भीतरघात की सियासत व कूटनीति है। इन देशों से व्यापार घाटा का मतलब है कि भारत में इन देशों से आयात ज्यादा है, जबकि इन देशों को भारत से निर्यात कम होने से है, खासकर ऊर्जा (तेल 80% आयातित) और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स क्षेत्र में।जहां चीन के साथ संकीर्ण निर्यात (कच्चा माल), बाजार बाधाएं, और सस्ते आयात की समस्या है। वहीं, रूस/यूएई से तेल आयात में वृद्धि, और निर्यात सम्बन्धी बाधाएं हैं। इस तरह से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वाले देशों के साथ घाटा 59% बढ़ा (2025-Q1) है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में कुल घाटा $25 बिलियन तक पहुंच चुका है। वित्त वर्ष (FY) 25 में चीन के साथ यह रिकॉर्ड उच्च स्तर है। जबकि सरकार पीएलआई (PLI) जैसी आकर्षक योजना से आयात कम करने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वाले देश कौन कौन से हैं जिनके साथ भारत का घाटा बढ़ा है, तो जवाब होगा कि भारत के एफटीए (FTA) देशों के साथ व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2025 (Q1 FY26) में 59.2% बढ़कर $26.6 बिलियन हो गया है। कहने का तातपर्य यह कि भारत में आयात 10% बढ़े जबकि निर्यात 9% गिरे, जो हमारी रणनीतिक आर्थिक चौकसी में कमी को दर्शाता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित देश भारत के विदेश व्यापार घाटे में योगदान दे रहे हैं। इन देश/समूह से कारोबारी घाटे का कारण/ट्रेंड निम्नलिखित हैं-

पहला, आसियान (ASEAN) समूह के देशों यानी सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड को निर्यात में 16.9% गिरावट (सिंगापुर -13.3%, मलेशिया -39.7%) आई।

दूसरा, यूएई से आयात बिल बढ़ा, जबकि निर्यात 2.1% गिरा।

तीसरा, दक्षिण कोरिया से आयात बढ़ोतरी हुई।

चतुर्थ, जापान से भी आयात बढ़ोतरी देखी गई।

पंचम, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में -8.7% से -10.9% कमी आई।

छठा, सऊदी अरब को भी निर्यात -8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

इसका कारण आसियान (ASEAN) के साथ पुनर्समझौता में देरी और आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल की वृद्धि हुई; जबकि निर्यात में कमी आई है। वहीं, FTA पुनः समझौता (renegotiation) भी लंबित है। शायद इसलिए सरकारी रणनीतियाँ बदली हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत 25,060 करोड़ रुपये की योजना 2025-31 तक चल रही, जिसमें ब्याज सब्वेंशन, क्रेडिट गारंटी और ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 (बिना समाप्ति तिथि) निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, SEZ को मजबूत करती है और RoDTEP जैसे स्कीम्स बहाल किए गए। जबकि चीन से घाटा कम करने हेतु पीएम नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है। वहीं, निर्यात बढ़ाने वाली योजनाएँ: (जैसे NIRYAT PROTSAHAN) MSME को लक्षित कर रही हैं, जो लंबी अवधि में अधिशेष की दिशा में ले जा सकती हैं। कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं, लेकिन सुधारों से 1-2% GDP पर CAD स्थिर रह सकता है।

वहीं, भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जो मुख्य रूप से MSME, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और पहली बार निर्यात करने वालों पर केंद्रित हैं। ये योजनाएं वित्तीय सहायता, लॉजिस्टिक्स सुधार और बाजार पहुंच को मजबूत करती हैं।

## प्रेरणा

# चांडाल से ब्रह्मबोध तकः गुरु की वास्तविक पहचान

भारतीय दर्शन की परंपरा में आदि शंकराचार्य का नाम केवल एक महान आचार्य के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की क्रांति के अग्रदूत के रूप में लिया जाता है। वे उस युग में अवतरित हुए जब कर्मकांड, जातिगत भेद और बाह्य आडंबर धर्म के केंद्र में आ चुके थे। ऐसे समय में उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से यह उद्घोष किया कि ब्रह्म एक है, अखंड है और वही समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उनका जीवन केवल ग्रंथों और शास्त्रार्थों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके अनुभव, घटनाएं और आत्मबोध ही उनके दर्शन की सजीव व्याख्या बन गए। काशी की वह प्रसिद्ध घटना, जिसमें एक चांडाल ने उन्हें सत्य का दर्पण दिखाया, इसी जीवंत दर्शन की चरम अभिव्यक्ति है।

बाल्यावस्था से ही शंकराचार्य असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि अल्पायु में ही उन्होंने वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता का गहन अध्ययन कर लिया था। उनका मन केवल शब्दों के अर्थ में नहीं अटका रहता था, बल्कि वे प्रत्येक श्लोक के पीछे छिपी अनुभूति को जीना चाहते थे। संन्यास धारण करने के बाद उन्होंने भारत के कोने-कोने में भ्रमण किया, विभिन्न मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ किए और तर्क के साथ-साथ करुणा के माध्यम से सत्य को प्रतिष्ठित किया। उनके लिए दर्शन कोई बौद्धिक खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग था।

काशी उस समय भी ज्ञान और साधना का प्रमुख केंद्र थी। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि चेतना की धारा मानी जाती थी। शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में अचानक एक चांडाल सामने आया, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर समझा जाता था और जिसका कार्य शव उठाना था। तत्कालीन सामाजिक संरचना में ऐसे व्यक्ति को अपवित्र माना जाता था। अनजाने में, शायद सामाजिक संस्कारवश, शंकराचार्य के मुख से निकल गया—"हटो, मार्ग छोड़ो।" यह एक क्षणिक वाक्य था, परंतु उसी क्षण ब्रह्मज्ञान की परीक्षा भी उपस्थित हो गई।

चांडाल ने न तो क्रोध किया, न अपमान का भाव दिखाया। उसके स्वर में अद्भुत शांति और गहराई थी। उसने प्रश्न किया—"आप किसे हटने को कह रहे हैं, इस नश्वर शरीर को या उस चेतना को जो इस शरीर में वास करती है? यदि शरीर हटे तो क्या चेतना हट जाएगी? और यदि चेतना हटे, तो क्या वह आपके कहने से हट सकती है?" यह प्रश्न साधारण नहीं था। इसमें उपनिषदों की गूंज थी, अद्वैत का सार था और आत्मबोध की स्पष्ट झलक थी।

शंकराचार्य वहीं ठिठक गए। उनके भीतर का आचार्य, दार्शनिक और साधक एक साथ जाग उठा। उन्होंने अनुभव किया कि जिस अद्वैत का वे प्रचार कर रहे हैं, उसकी कसौटी स्वयं उनके सामने खड़ी है। यदि ब्रह्म सर्वत्र है, यदि वही चेतना चांडाल में भी उतनी ही व्याप्त है जितनी एक ब्राह्मण में, तो ऊंच-नीच का भेद कैसे टिक सकता है? यह केवल बौद्धिक स्वीकृति का प्रश्न नहीं था, बल्कि आचरण की अग्निपरीक्षा थी।

क्षण भर में शंकराचार्य का अहं गल गया। वे समझ गए कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं, बल्कि किसी उच्च अवस्था का ज्ञानी है। उन्होंने बिना किसी संकोच के उसी चांडाल के चरणों में प्रणाम किया। यह दृश्य उनके शिष्यों के लिए चौंकाने वाला था। जिस आचार्य को वे देवतुल्य मानते थे, वह एक तथाकथित अस्पृश्य के चरणों में झुक गया था। उनके मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा।

शंकराचार्य ने शिष्यों की ओर देखकर कहा कि गुरु की पहचान जाति, वेश या सामाजिक स्थिति से नहीं होती। जो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य का बोध करा दे, वही गुरु है। उस क्षण उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अद्वैत वेदांत केवल शास्त्रों में लिखी अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य सत्य है। यदि हम केवल बोलें कि ब्रह्म एक है, पर व्यवहार में भेद करें, तो वह दर्शन खोखला रह जाता है।

कहा जाता है कि इसी अनुभव से प्रेरित होकर शंकराचार्य ने 'मनीषा पंचकम्' की रचना की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि उसे आत्मबोध हो गया है, तो वह मेरा गुरु है। यह घोषणा उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थी। यह केवल सामाजिक समानता का संदेश नहीं था, बल्कि चेतना की एकता का उद्घोष था।

इस घटना का महत्व आज के समय में और भी बढ़ जाता है। हम आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक की बातें करते हैं, परंतु भीतर कहीं न कहीं भेदभाव, अहं और श्रेष्ठता-बोध अब भी जीवित है। शंकराचार्य की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से जन्म लेता है। जब तक हम अपने भीतर के अहं को नहीं पहचानते और उसे त्यागते नहीं, तब तक ब्रह्मबोध केवल शब्दों में ही रहेगा।

चांडाल और शंकराचार्य का यह संवाद गुरु-शिष्य की पारंपरिक परिभाषा को भी तोड़ता है। यहां कोई औपचारिक दीक्षा नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई परंपरागत गुरु-गद्दी नहीं थी। केवल एक प्रश्न था, जो सीधे आत्मा को छू गया। यही प्रश्न शंकराचार्य के लिए गुरु बन गया। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में गुरु को व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था माना गया है।

अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर प्राणी में समान रूप से विद्यमान है। जो इसे पहचान लेता है, वही ज्ञानी है, वही गुरु है। आदि शंकराचार्य का महानत्व इसी में निहित है कि उन्होंने न केवल इस सत्य को जाना, बल्कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और अपने आचरण से उसे प्रमाणित किया। यही कारण है कि वे आज भी केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि सत्यबोध के शाश्वत गुरु के रूप में स्मरण किए जाते हैं।

# पारिस्थितिकीय संतुलन न बिगाड़े सौर ऊर्जा मुहिम

राजस्थान के पश्चिमी अंचल में इन दिनों एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है, जो आधुनिक विकास के मॉडल पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करती है। बीकानेर और जैसलमेर के रेतीले धोरों से उठा 'खेजड़ी और ओरण बचाओ आंदोलन' महज़ चंद पेड़ों को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की अंतिम पुकार है, जिसने सदियों से थार के मरुस्थल को जीवंत बनाए रखा है। जिस 'हरित ऊर्जा' को हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में देख रहे हैं, वही सौर परियोजनाएं आज राजस्थान के 'ओरण' और राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' के लिए अस्तित्व का संकट बन गई हैं। मरुस्थल के पर्यावरण में 'ओरण' की महत्ता को वैज्ञानिक और सामाजिक, दोनों ही धरातलों पर समझना आवश्यक है। ओरण वे सामुदायिक वन क्षेत्र हैं, जिन्हें लोक देवताओं के नाम पर समर्पित कर दशकों और सदियों से संरक्षित किया गया है। सरकारी दस्तावेजों में भले ही इन्हें 'वेस्टलैंड' यानी बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, लेकिन पारिस्थितिकी विज्ञान के नजरिए से ये 'बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट' हैं। राजस्थान में लगभग 25,000 ओरण हैं, जो करीब 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। ये क्षेत्र न केवल दुर्लभ वनस्पतियों के घर हैं, बल्कि लुप्तप्राय जीवों के लिए अंतिम शरणस्थली भी हैं। यहां की जैव-विविधता अन्य मरुस्थलीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है, जो पूरे क्षेत्र के सूक्ष्म-जलवायु को नियंत्रित करती है।

थार मरुस्थल में मानसून का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओरण और खेजड़ी का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो धूल भरी आंधियों की तीव्रता उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, यहां तक कि दिल्ली-एनसीआर तक, कई गुना बढ़ जाएगी। ओरण की घास और पेड़ों की कमी का सीधा अर्थ है—रेत का अनियंत्रित प्रसार।

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि ओरण को 'डीम्ड फॉरेस्ट' माना जाए, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें आज भी 'बंजर' के रूप में दर्ज किया जाना एक बड़ी प्रशासनिक चूक है। इसी चूक का फायदा उठाकर ऊर्जा कंपनियां इन जमीनों को कौड़ियों के दाम पर लीज पर ले रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सौर परियोजनाओं के विस्तार के कारण केवल पश्चिमी राजस्थान में 26 लाख से अधिक खेजड़ी के पेड़ काटे गए हैं। वैज्ञानिक शोध जैसे फोटोवोल्टिक हीट आइलैंड इफेक्ट संबंधी अध्ययन चेतावनी देते हैं कि सौर पैनलों का अत्यधिक जमाव स्थानीय तापमान को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। यह ऊष्मा मरुस्थल के नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रही है। इसके अतिरिक्त, 'लेक इफेक्ट' के कारण आकाश में उड़ते पक्षियों को ऊपर से ये नीले पैनल जलस्रोत का भ्रम देते हैं, जिससे टकराकर उनकी मृत्यु हो रही है।

जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो थार मरुस्थल में पानी की एक-एक बूंद स्वर्ण के समान है। लेकिन एक विशाल सौर परियोजना को सुचारु रखने के लिए पैनलों की सफाई हेतु प्रति सप्ताह लाखों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह पानी उसी भूजल स्रोत से खींचा जा रहा है, जो स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों की जीवनरेखा है। जब ओरण की ज़मीन पर कंक्रीट के ढांचे और पैनल बिछ जाते हैं, तो वर्षा जल के संचयन की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन के चलते जहां मरुस्थलीकरण को रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए, वहां खेजड़ी जैसे पेड़ों को काटना आत्मघाती कदम है। खेजड़ी की जड़ें ज़मीन के 30 मीटर नीचे तक जाकर मिट्टी को थामे रखती हैं और धूल भरी आंधियों की गति को नियंत्रित करती हैं। यदि ये 'प्राकृतिक दीवारें' ढह गईं, तो मरुस्थल का विस्तार अरावली की सीमाओं को लांघकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि सौर ऊर्जा का विकास 'विकेंद्रीकृत' हो—उपजाऊ ओरण और मारू वनों के बजाय छतों और बंजर पहाड़ों का उपयोग किया जाए।

विकास का पैमाना केवल 'मेगावाट' न हो, बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी हो जो सदियों से हमें ऑक्सीजन, चारा और आश्रय देता आया है। मरुभूमि के पर्यावरण, उसकी जैव-विविधता और अनोखी जलवायु को बचाने के लिए ओरण को बचाना अब केवल एक क्षेत्रीय मांग नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय आपातकाल बन चुका है। समझना होगा कि बिना खेजड़ी और ओरण के, राजस्थान का मरुस्थल केवल एक तपता हुआ सौर-कांच का घर बनकर रह जाएगा, जहां जीवन के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

यह समय नीति-निर्माताओं के लिए आत्ममंथन का है कि क्या हम एक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करके प्राप्त की गई बिजली को वास्तव में 'हरित ऊर्जा' कह सकते हैं? मरुभूमि की जैव-विविधता और ओरण की पवित्रता को बचाना अब केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक नैतिक उत्तरदायित्व है।

## अभियान

# जब ठाकुर जी कहें "अभी ठहरो": प्रतीक्षा भी बांके बिहारी की सच्ची भक्ति है

वृंदावन का नाम लेते ही मन अपने आप झुक जाता है। यहां भक्ति कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। यहां आना भी कृपा है और रुक जाना भी। ठाकुर बांके बिहारी की ओर बढ़ते कदम केवल मंदिर की दिशा में नहीं जाते, वे भीतर की ओर भी मुड़ते हैं। नए साल की आहट के साथ जब लाखों हृदयों में एक ही इच्छा जन्म लेती है—"साल की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से हो"—तो यह भावना अत्यंत पावन होती है। लेकिन भक्ति का मार्ग केवल उत्साह से नहीं चलता, उसमें संयम, समझ और समर्पण भी उतना ही आवश्यक होता है।

इन दिनों वृंदावन की गलियों में जो दृश्य है, वह भक्ति की तीव्रता का प्रमाण जरूर है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि कहीं यह तीव्रता स्वयं भक्त के लिए कठिनाई न बन जाए। रोज़ चार से पाँच लाख श्रद्धालुओं का वृंदावन पहुँचना साधारण बात नहीं है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास यह संख्या और भी बढ़ जाती है। मंदिर परिसर छोटा है, रास्ते संकरे हैं, और आस्था अथाह। ऐसे में प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को अगर ध्यान से सुना जाए, तो उसमें रोक नहीं, करुणा बोलती है।

29 दिसंबर से 5 जनवरी तक भक्तों से अपील की गई है कि अत्यंत आवश्यक न हो तो मंदिर आने से बचें। यह बात सुनकर मन को ठेस लग सकती है—"क्या भक्ति पर भी रोक?" लेकिन वृंदावन की भक्ति ऐसी नहीं है जो आदेशों से टकराए। यहां तो हर संकेत को ठाकुर जी की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाता है। अगर परिस्थितियाँ कह रही हैं कि अभी मत आओ, तो इसे ठाकुर जी का ही संकेत समझना चाहिए—"भक्त सुरक्षित रहे, यही मेरी लीला है।"

बांके बिहारी जी का स्वभाव ही बड़ा ललित है। वे अपने भक्तों को परीक्षा में नहीं डालते, वे उन्हें संभालते हैं। भीड़, धक्का-मुक्की, उमस, थकान—ये सब शरीर को कष्ट देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर धर्म का साधन है। अगर शरीर ही संकट में पड़ जाए, तो भक्ति भी बोझ बन जाती है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अस्वस्थ लोग इस भीड़ में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। चक्कर आना, सांस फूलना, घबराहट होना—ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। क्या ठाकुर जी यह चाहेंगे कि उनके दर्शन के लिए कोई भक्त पीड़ा सहे? नहीं। उनका प्रेम ऐसा नहीं है।

वृंदावन में एक बात बहुत कही जाती है—"वृंदावन वही आता है, जिसे बुलावा आता है।" बुलावा केवल मन से नहीं, परिस्थिति से भी आता है। कभी-कभी बुलावा प्रतीक्षा का होता है। प्रतीक्षा भी भक्ति का ही एक रूप है। जब भक्त रुकना सीख लेता है, तब उसका समर्पण और गहरा हो जाता है। जिद भक्ति नहीं होती, समर्पण भक्ति होता है।

भीड़ के दिनों में दर्शन का स्वरूप भी बदल जाता है। बांके बिहारी मंदिर में वैसे भी लंबे समय तक मूर्ति के सामने खड़े रहने की परंपरा नहीं है। अत्यधिक भीड़ होने पर सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। कई बार तो ठाकुर जी के सामने दो पल हाथ जोड़ने का अवसर भी नहीं मिल पाता। मन में भाव होते हैं, आंखों में नमी होती है, लेकिन दर्शन एक झलक में ही पूरे हो जाते हैं। तब मन कहता है—"काश थोड़ा और ठहर पाते।" इतनी कठिन यात्रा के बाद भी मन तृप्त न हो, तो भीतर खालीपन रह जाता है। जबकि वृंदावन तो तृप्ति का स्थान है, यहां आकर मन भर जाना चाहिए।

भीड़ के साथ चिंता भी आती है—पर्स खो न जाए, मोबाइल सुरक्षित रहे, जूते मिलेंगे या नहीं। मंदिर के नियमों के अनुसार कई वस्तुएं अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती, जिससे भक्तों को बाहर सामान छोड़ना पड़ता है। अत्यधिक भीड़ में यह चिंता और बढ़ जाती है। जब मन बार-बार भटकता है, तो भक्ति की धारा टूटने लगती है। ठाकुर जी तो शांत मन में बसते हैं।

ऐसे समय में घर पर बैठकर किया गया स्मरण भी उतना ही मूल्यवान है। नाम जप, भजन, कथा, ठाकुर जी की लीला का चिंतन—ये सब भी वृंदावन की ही सेवा हैं। संत कहते हैं कि जिसने मन में वृंदावन बसा लिया, उसके लिए दूरी कोई अर्थ नहीं रखती। अगर मन से "राधे-राधे" निकला है, तो वह वृंदावन की हर गली से होकर ठाकुर जी तक पहुँचता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि बांके बिहारी जी किसी एक तारीख के बंधन में नहीं हैं। नए साल के बाद भी वही ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, वही मुस्कान होगी, वही कृपा होगी। जनवरी के बाद फाल्गुन आएगा, बसंत आएगा, होली आएगी—जब वृंदावन रंग, रस और प्रेम से भर जाएगा। तब दर्शन कहीं अधिक सहज, शांत और रसपूर्ण होंगे। तब न धक्का होगा, न घबराहट—सिर्फ ठाकुर जी और भक्त के बीच का भाव होगा।

भक्ति का अर्थ केवल चलकर मंदिर पहुँचना नहीं है। कई बार रुक जाना, किसी को कष्ट से बचा लेना, अपने माता-पिता या बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना—यह सब भी भक्ति ही है। ठाकुर जी को यह दिखावा नहीं चाहिए कि भक्त कितनी भीड़ में घुस गया। उन्हें तो यह भाव प्रिय है कि भक्त ने समझदारी दिखाई, संयम रखा और प्रेम बनाए रखा।

नया साल भी कोई जादुई तिथि नहीं है कि उसी दिन सब कुछ शुभ हो जाए। शुभता मन की अवस्था से आती है। अगर मन में शांति है, विवेक है और समर्पण है, तो हर दिन नया साल है। अगर इस बार 1 जनवरी को बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वर्ष अशुभ हो गया। ठाकुर जी की कृपा तारीख देखकर नहीं बरसती, भाव देखकर बरसती है।

वृंदावन की भक्ति में एक गहरा रहस्य है—यहां जल्दी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है, वह स्थायी होता है। जो भक्त धैर्य रखता है, वही वास्तविक रस पाता है। अगर आज परिस्थितियाँ कह रही हैं कि "अभी मत आओ", तो इसे टालना नहीं, स्वीकार करना चाहिए। यही स्वीकार भाव को परिपक्व बनाता है।

इसलिए अगर आपने भी इन दिनों बांके बिहारी मंदिर जाने का प्लान बनाया है, तो थोड़ा ठहर जाइए। इसे त्याग मत समझिए, इसे ठाकुर जी पर भरोसा समझिए। प्रशासन की सलाह को अपनाइए, अपने और अपनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। जब समय अनुकूल होगा, जब भीड़ कम होगी, जब आप निश्चिंत होकर वृंदावन की गलियों में चल पाएंगे—तब वही ठाकुर बांके बिहारी स्वयं बुलाएंगे।

और जब वह बुलावा आएगा, तब दर्शन केवल आंखों से नहीं होंगे, आत्मा से होंगे।

क्योंकि वृंदावन में भीड़ नहीं, भाव चलता है।

और बांके बिहारी भाव के ही भगवान हैं।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की केंद्रीय बजट पर पत्रकार वार्ता

**▸▸ यह केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के लिए क्वांटम जंप देने वाला है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

**▸▸ ग्राम विकास से लेकर गिफ्ट सिटी तक के क्षेत्रों को सर्वग्राही विकास से कवर करने वाला केंद्रीय बजट गुजरात के लिए लाभदायक**

**▸▸ गिफ्ट सिटी में दिए गए टैक्स हॉलिडे से निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ करेंगे निवेश**

**▸▸ कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने को तैयार गुजरात के खेल क्षेत्र को खेलो इंडिया मिशन से मिलेगी तेजी**

**▸▸ राष्ट्रीय वृद्धि में गुजरात के अहम योगदान के चलते 16वें वित्त आयोग के तहत राज्य का सेंट्रल डिवॉल्युशन 3.75 फीसदी किया गया**

**▸▸ पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने का लाभ गुजरात के छोटे शहरों को भी मिलेगा**

**(जीएनएस)।** गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 को तीन मुख्य कर्तव्यों के आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने वाला बजट करार दिया है।

उन्होंने इन तीन कर्तव्यों पर रोशनी डालते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देते हुए टिकाऊ विकास, लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर क्षमता निर्माण से देश की समृद्धि में सक्रिय जनभागीदारी और 'सबका साथ, सबका विकास' को और अधिक गति देने की प्रतिबद्धता इस बजट में प्रतिबिंबित हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करने के साथ-साथ गुजरात को इस बजट से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को आगे बढ़ाने वाला विकसित भारत के लिए क्वांटम जंप (एक बड़ी छलांग) देने वाला बजट बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में गति कर रहा है, तब यह बजट

**तीन कर्तव्यों के आधार पर विकसित भारत की मजबुत बुनियाद तैयार करने वाला बजट**

▸▸ आर्थिक वृद्धि को गति देते हुए टिकाऊ विकास

▸▸ लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर क्षमता निर्माण से देश की समृद्धि में सक्रिय जनभागीदारी

▸▸ 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता

विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन वाले बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से देश को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात फार्मास्युटिकल क्षेत्र में देश का अगुवा है और बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम का लाभ राज्य के फार्मा सेक्टर को भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई 6 योजनाओं का लाभ राज्य के टेक्सटाइल क्षेत्र को गति देगा।

उन्होंने राज्य के 42.9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस वर्ष के बजट में 'चेम्पियन एमएसएमई' के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की गई है। इससे एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा और लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात चार सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसे बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के माल ढुलाई मार्ग के नेटवर्क से लॉजिस्टिक सपोर्ट सुदृढ़ हुआ है, अब पूर्वी भारत में स्थित दानकुनी से हमारी टेक्सटाइल सिटी सूरत तक के नए समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) से राज्य के व्यापार-उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तेज लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने देश के फिनटेक हब गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में दस वर्ष के टैक्स हॉलिडे यानी कर अवकाश को बढ़ाकर 20 वर्ष करने की घोषणा का स्वागत किया।

इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस टैक्स हॉलिडे के चलते गिफ्ट सिटी में निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के शहरों के ग्रोथ हब बनने का जिक्र करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की घोषणा से हमारे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों का विकास भी तेज गति से होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसे बजट में घोषित खेलो इंडिया मिशन कार्यक्रम से और अधिक प्रेरणा और बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वृद्धि में गुजरात के महत्वपूर्ण योगदान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत गुजरात के लिए सेंट्रल डिवॉल्युशन (केंद्रीय करों की विभाज्य निधि में गुजरात का हिस्सा) 3.48 फीसदी से बढ़ाकर3.75 फीसदी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति मिलेगी।

युवाओं के लिए रोजगार निर्माण के नए द्वार खोलने वाली अनोखी योजना के बारे में उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, इसके लिए विशेष एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके लिए देश में 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आशा जताई कि गुजरात के महत्वाकांक्षी युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस विकासोन्मुखी बजट का लाभ प्राप्त कर गुजरात डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड से विकसित भारत के निर्माण की अगुवाई करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव श्री अजय कुमार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

## आस्था से सेवा तक का सफर: श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल 7 फरवरी को करेगा 500वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन

**(जीएनएस)।** सूरत में धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक अनूठा और प्रेरणादायी उदाहरण बन चुके श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल द्वारा शनिवार, 7 फरवरी 2026 को अपने 500वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि बीते साढ़े तीन वर्षों की उस सतत साधना और सेवा यात्रा का उत्सव है, जिसने हजारों लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श किया है। मंडल की स्थापना 6 अगस्त 2022 को हुई थी और अल्प समय में ही इस संस्था ने सूरत ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी अलग पहचान बना ली है।

श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने भक्ति को केवल पाठ और पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सेवा के माध्यम से समाज से जोड़ा। मंडल के प्रमुख मनोजभाई ने बताया कि स्थापना के

बाद से अब तक मंडल द्वारा सूरत सहित विभिन्न गांवों की गौशालाओं को लगभग 23 से 25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि गौ माता के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की उस भावना का प्रतीक है, जिसे मंडल ने अपने मूल उद्देश्य के रूप में अपनाया है। मंडल का स्पष्ट संकल्प है कि प्रत्येक सुंदरकांड पाठ से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि गौ सेवा के लिए समर्पित की जाएगी, जिससे सेवा और भक्ति के बीच का संबंध और भी मजबूत हो सके।

सुंदरकांड पाठ के माध्यम से एकत्रित सेवा राशि का उपयोग केवल गौ सेवा तक सीमित नहीं रहा है। मंडल ने समय-समय पर मानव सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अनाथालयों में भोजन सेवा, वृद्धाश्रमों में निवासरत बुजुर्गों के लिए भोजन व्यवस्था, बेघर और वंचित लोगों तक भोजन पहुंचाना तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के आश्रमों में सेवा कार्य, मंडल की नियमित गतिविधियों का हिस्सा रहे हैं। इन कार्यों के माध्यम से मंडल ने यह संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति वही है, जो पीड़ित और जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सके।

मानव सेवा के प्रति मंडल की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण हॉस्पिटल छायड़ों में मशीन हेतु समर्पित की गई 5 लाख रुपये की सहायता राशि है। यह पहल उन मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत बनी, जो सीमित संसाधनों के बीच इलाज के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। ऐसे कार्यों ने श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल को एक धार्मिक संस्था के साथ-साथ एक सामाजिक सेवा संगठन के रूप में भी स्थापित किया है।

500वें सुंदरकांड पाठ के अवसर पर मंडल ने उन सभी पाठ आयोजकों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने समय-समय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर बालाजी महाराज का गुणगान किया और साथ ही गौ सेवा के लिए सहयोग राशि प्रदान की। मंडल का मानना है कि यह यात्रा अकेले किसी एक व्यक्ति या समिति की नहीं, बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं और सदस्यों की सामूहिक साधना का परिणाम है, जिन्होंने नियमित रूप से पाठ में उपस्थित होकर अपना कीमती समय बाबा और गौ माता की सेवा में समर्पित किया।

इन साढ़े तीन वर्षों में श्री केसरी नंदन सुंदरकांड मंडल की यात्रा यह सिद्ध करती है कि जब धार्मिक आस्था को सेवा और संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका प्रभाव समाज में दूर तक जाता है। 500वें सुंदरकांड पाठ का आयोजन इसी सतत प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो आने वाले समय में और अधिक सेवा कार्यों के लिए प्रेरणा बनेगा। सूरत की धार्मिक और सामाजिक जीवनधारा में यह आयोजन न केवल श्रद्धा का प्रतीक होगा, बल्कि यह भी याद दिलाएगा कि भक्ति का सबसे सुंदर रूप सेवा ही है।

## सरल टैक्स व्यवस्था की ओर बड़ा कदम, बजट विश्लेषण में व्यापार जगत ने जताई संतुष्टि

**(जीएनएस)।** सूरत। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देशभर में जहां अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं सूरत के व्यापार और उद्योग जगत ने इस बजट को टैक्स सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'पोस्ट बजट एनालिसिस' कार्यक्रम में कर विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उद्यमियों ने बजट के प्रावधानों पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर देश के जाने-माने टैक्स एक्सपर्ट और अधिवक्ता मुकेश पटेल ने बजट के टैक्स संबंधी प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने टैक्स सिस्टम को अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं, जिसका सीधा लाभ व्यापारियों और करदाताओं को मिलेगा।

मुकेश पटेल ने अपने विश्लेषण में विशेष रूप से टीडीएस और टीसीएस से जुड़े प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि अब तक टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि कई बार एक ही लेन-देन पर दोहरी कर कटौती या वसूली की स्थिति बन जाती थी, जिससे न केवल व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था, बल्कि विवाद और कानूनी अड़चनें भी बढ़ती थीं। नए बजट में इस समस्या को गंभीरता से समझते हुए 'नो डबल टैक्सेशन' की दिशा में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब एक ही ट्रांजेक्शन पर दो बार टैक्स नहीं लगेगा, जिससे उद्योग जगत और व्यक्तिगत करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स नियमों को केवल कागजी सुधारों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने योग्य बनाया गया है। टैक्स सिस्टम को अधिक प्रैक्टिकल बनाने का यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जटिल नियमों के कारण छोटे और मध्यम व्यापारियों को अक्सर अनजाने में गलतियां हो जाती थीं, जिनका खामियाजा उन्हें नोटिस, पेनल्टी और मुकदमों के रूप में भुगतना पड़ता था। नए प्रावधानों से ऐसी स्थितियों में कमी आने की उम्मीद है और टैक्सपेयर तथा टैक्स डिपार्टमेंट के बीच विश्वास का माहौल बनेगा।

कार्यक्रम में रिटर्न फाइलिंग से जुड़े बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिवक्ता पटेल ने बताया कि बजट में इस संबंध में दो ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, जिन्हें क्रांतिकारी कहा जा सकता है। अब तक यदि किसी करदाता ने घाटे यानी लॉस का रिटर्न दाखिल किया होता था, तो वह उसे बाद में अपडेट नहीं कर पाता था, भले ही बाद में आंकड़ों में सुधार की जरूरत महसूस हो। नए प्रावधान के तहत यदि घाटा कम होता है, तो लॉस रिटर्न को भी अपडेट किया जा सकेगा। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो ईमानदारी से अपनी आय और घाटे का विवरण देना चाहते हैं। इसके अलावा री-असेसमेंट की प्रक्रिया में भी करदाताओं को राहत देने की कोशिश की गई है। अब यदि किसी करदाता को री-असेसमेंट नोटिस मिलता है, तो भी उसे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अवसर मिल सकता है। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक री-असेसमेंट नोटिस मिलते ही करदाताओं में भय का माहौल बन जाता था और सुधार की गुंजाइश बहुत सीमित रह जाती थी।

## ग्रीन स्टील की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि, AM/NS India को नई टैक्सोनॉमी के तहत देश का पहला प्रमाणन

**(जीएनएस)।** सूरत। भारत के इस्पात उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) इस्पात मंत्रालय की नई ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ग्रीन स्टील सर्टीफिकेशन प्राप्त करने वाली देश की पहली एकीकृत इस्पात उत्पादक कंपनी बन गई है। गुजरात के हजीरा स्थित अपने प्रमुख संयंत्र के माध्यम से कंपनी ने यह मान्यता हासिल कर न केवल भारतीय इस्पात उद्योग में नया मानक स्थापित किया है, बल्कि देश को टिकाऊ और लो-कार्बन भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी बढ़ाया है।

इस सर्टीफिकेशन के तहत AM/NS India के हॉट रोल्ड (HR) कॉयल्स और शीट्स को 4-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जबकि कोल्ड रोल्ड (CR) कॉयल्स और शीट्स को 3-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब इन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित ग्रीन स्टील के रूप में मान्यता मिल गई है, जिससे इन क्षेत्रों से जुड़े ग्राहक अपनी सप्लाई चेन में स्कोप-3 तक के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होंगे।

ग्रीन स्टील सर्टीफिकेशन की पात्रता इस्पात उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता पर आधारित होती है। इसके लिए तैयार इस्पात के प्रति टन उत्सर्जन 2.2 टन CO समतुल्य से कम होना अनिवार्य है। इस सीमा के भीतर आने वाले उत्पादों को तीन-स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत 3-स्टार, 4-स्टार या 5-स्टार रेटिंग दी जाती है। AM/NS India को यह मान्यता नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST) द्वारा की गई एक कठोर और विस्तृत ऑडिट प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के प्रमुख फ्लैट स्टील पोर्टफोलियो को सभी ग्रीन स्टील मानकों पर परखा गया।

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए AM/NS India के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप ऊम्मेन ने कहा कि भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी इस्पात उद्योग के भविष्य और डी-कार्बनाइजेशन की दिशा में एक स्पष्ट और मजबूत रोडमैप प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि AM/NS India लगातार अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए लो-कार्बन स्टील उत्पादन की दिशा में काम कर रही है और यह नया फ्रेमवर्क कंपनी की इस प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है।

## विश्व पटल पर सूरत सुथार समाज का गौरव: उद्योग सेवा और संस्कार का संगम बने सुखदेव जांगिड़

**(जीएनएस)।** सूरत। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योग और तकनीक की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके भामाशाह सुखदेव जांगिड़ के सूरत आगमन पर सूरत सुथार समाज में उत्साह, गौरव और सम्मान का वातावरण देखने को मिला। समाज द्वारा उनके लिए एक भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन 4 फरवरी को राजस्थान विश्वकर्मा मंदिर, भटार में किया गया, जहां समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं, संतों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। यह

आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि समाज के आत्मविश्वास, एकजुटता और भविष्य की दिशा को दर्शाने वाला अवसर बन गया। लंदन में रहकर विश्व के कई देशों में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कारोबार संचालित कर रहे सुखदेव जांगिड़ आज अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत में एक सशक्त नाम माने जाते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। इस उपलब्धि को समाज ने केवल एक कारोबारी सफलता नहीं, बल्कि सुथार समाज की प्रतिभा, परिश्रम और वैश्विक क्षमता का प्रतीक माना। इसी भावना के साथ उनके सूरत आगमन को समाज ने गौरवपूर्ण क्षण के रूप में मनाया।

समारोह को संबोधित करते हुए सुखदेव जांगिड़ ने सादगी और आत्मीयता के साथ अपने विचार रखे। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी से आगे आने, बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, उद्यमिता और सेवा—ये तीन स्तंभ किसी भी समाज और राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं।

## सोना वायदा में 1456 रुपये का ऊछाल: चांदी वायदा में 16955 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 77 रुपये फिसला

**(जीएनएस)।** मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 129269.47 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 44630.17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 84637.25 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37817 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3359.46 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 38425.89 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 150299 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151500 रुपये और नीचे में 147000 रुपये पर पहुंचकर, 149244 रुपये के पिछले बंद के सामने 1456 रुपये या 0.98 फीसदी की तेजी के संग 150700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1101 रुपये या 0.87 फीसदी औंधकर 125099 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 134 रुपये या 0.85 फीसदी औंधकर 15576 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 148500 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150942 रुपये और नीचे में 146900 रुपये पर पहुंचकर, 207 रुपये या 0.14 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 154800 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 155949 रुपये और नीचे में 146605 रुपये पर पहुंचकर, 155962 रुपये के पिछले बंद के सामने 1915 रुपये या 1.23 फीसदी औंधकर 154047 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 258096 रुपये के भाव पर खूलकर, 258096 रुपये के दिन के उच्च और 239000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268850 रुपये के पिछले बंद के सामने 16955 रुपये या 6.31 फीसदी लुढ़ककर 251895 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 17759 रुपये या 6.42 फीसदी की गिरावट के साथ 259031 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 17919 रुपये या 6.47 फीसदी गिरकर 259000 रुपये प्रति किलो के

**कमोडिटी वायदाओं में 44630.17 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 84637.25 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 38425.89 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37817 पॉइंट के स्तर पर**

भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 4299.20 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 9.6 रुपये या 0.77 फीसदी गिरकर 1235 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.54 फीसदी औंधकर 319.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 1.4 रुपये या 0.45 फीसदी औंधकर 307.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 85 पैसे या 0.45 फीसदी की नरमी के साथ 189.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1899.61 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5798 रुपये के भाव पर खूलकर, 5831 रुपये के दिन के उच्च और 5750 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 77 रुपये या 1.31 फीसदी गिरकर 5814 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 76 रुपये या 1.29 फीसदी गिरकर 5816 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा।

इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 323.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 323.7 रुपये और नीचे में 308.6 रुपये पर पहुंचकर, 315.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.4 रुपये या 0.76 फीसदी औंधकर 312.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 2.4 रुपये या 0.76 फीसदी औंधकर 313 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 981 रुपये पर खूलकर, 2.4 रुपये या 0.24 फीसदी बढ़कर 983 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 20908.11 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 17517.77 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3453.82 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 445.59 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 27.39 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 372.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 500.66 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1388.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9509 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 66614 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31231 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 421576 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 52535 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8449 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21919 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 61508 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17056 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 15615 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 37957 पॉइंट पर खूलकर, 38400 के उच्च और 37328 के नीचले स्तर को छूकर, 1313 पॉइंट घटकर 37817 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 51.2 रुपये की गिरावट के साथ 244.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 50 पैसे के सुधार के साथ 29.15 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 376.5 रुपये की गिरावट के साथ 10374.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6244 रुपये की गिरावट के साथ 14307.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.75 रुपये की गिरावट के साथ 36.99 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.31 रुपये की गिरावट के साथ 2.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 27.2 रुपये की बढ़त के साथ 232.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 30 पैसे के सुधार के साथ 27.25 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 189.5 रुपये की बढ़त के साथ 7778.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7763.5 रुपये की बढ़त के साथ 30250 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 63 पैसे के सुधार के साथ 37.61 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 53 पैसे की नरमी के साथ 7 रुपये हुआ।

# खेड़ा जिले के विकास पथ पर एक और मील का पत्थर

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने फागवेल की धरती से खेड़ा जिले को 348 करोड़ रुपए से अधिक के 31 विकास कार्यों की भेंट दी

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नवगठित फागवेल तहसील का शुभारंभ किया

▸▸ फागवेल में आज विकास का नया सूरज उगा है, विकास कार्यों की भेंट मिलने से इस क्षेत्र का होगा कायापलट : कैबिनेट मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी

▸▸ खेड़ा जिला 'गोल्डन लीफ' से अब 'गोल्डन डेवलपमेंट' की दिशा में अग्रसर : राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिड़ा

**मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2002 में फागवेल की पवित्र धरा से ही गुजरात गौरव यात्रा शुरू कर विकास की नींव रखी थी

▸▸ 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' के तहत राज्य के 114 गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी

▸▸ फागवेल तालुका सेवा सदन के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है और 1 वर्ष के भीतर ही लोगों को आधुनिक कार्यालय की सुविधा प्राप्त हो जाएगी

**(जीएनएस)।** गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को खेड़ा जिले के फागवेल से वीर भाथीजी महाराज के चरणों में शीश नवाकर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए 348 करोड़ रुपए से अधिक के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने यह घोषणा की कि नवगठित फागवेल तहसील के प्रशासन को गति देने के लिए अत्याधुनिक तालुका सेवा सदन का निर्माण एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा।

इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फागवेल शौर्य और श्रद्धा की पवित्र धरती है, जिसे न केवल गुजरात, बल्कि पूरा देश जानता है। वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की अस्मिता को उजागर करने के लिए 'गुजरात गौरव यात्रा' की शुरुआत यहीं से की थी। आज वह विकास यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी




ने हमेशा अस्मिता, संस्कृति और सनातन धर्म का गौरव उजागर किया है। सोमनाथ की रक्षा करने वाले वीर हमीरजी गोहिल और गौरक्षा के लिए बलिदान देने वाले भाथीजी महाराज जैसी विभूतियों को गौरव देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विकास की राजनीति से विकास का एक नया इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास पर बल देते हुए कहा कि शहरीकरण के बोझ को कम करने के लिए गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तहसील मुख्यालय वाले 114 ऐसे गांवों के विकास के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' लागू की है, जहां नगर पालिका नहीं है।

उन्होंने कहा कि आगामी समय में इस योजना का दायरा बढ़ाकर 10,000 से अधिक आबादी वाले बड़े गांवों को भी इस योजना के तहत शामिल कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के विजन का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का इस वर्ष का बजट 'कर्तव्य' पर आधारित है। उन्होंने सभी लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित 'वोकल फॉर लोकल' और 'हर घर स्वदेशी' के मंत्र को अपनाकर विकसित खेड़ा से विकसित गुजरात और विकसित गुजरात से विकसित भारत की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया।

कैबिनेट मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने खेड़ा जिले के आस्था के केंद्र फागवेल में भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए वीर भाथीजी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि इस पवित्र धाम में आज विकास का नया सूरज उगा है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई, जलापूर्ति और ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं जैसे विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से फागवेल और खेड़ा जिले का कायापलट होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नई तहसील बनने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी और जनता की सुविधा में वृद्धि होगी।

श्री सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को चरितार्थ कर रही है। उन्होंने नागरिकों से सरकार के इस विकास के यज्ञ में शामिल होकर जिले के गौरवशाली बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की।

राज्य राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिड़ा ने कहा कि कपड़वंज की पवित्र धरा पर आज शक्ति, भक्ति और विकास का त्रिवेण संगम रचा है। उन्होंने कहा कि जो खेड़ा जिला पहले केवल 'गोल्डन लीफ' (तंबाकू) के लिए जाना जाता था, आज वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 'गोल्डन डेवलपमेंट' की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सरलता और जनोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए गठित की गई नई फागवेल तहसील से 169 वर्ग किमी क्षेत्र के नागरिकों के लिए तहसील मुख्यालय की दूरी कम हो जाएगी और सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने जिले में सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों के उल्लेख के साथ विकास कार्यों से होने वाले बदलाव की बात भी कही।

बालासिनोर के विधायक श्री मानसिंह चौहान और जिला कलेक्टर श्री अमित प्रकाश यादव ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा दी। निवासी अपर कलेक्टर श्री जे.बी. देसाई ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फागवेल तालुका सेवा सदन के भूमि आवंटन का आदेश पत्र तहसीलदार और टीडीओ को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने आज जिन विकास कार्यों की भेंट दी उनमें 234 करोड़ रुपए से अधिक के 13 कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ रुपए से अधिक के 18 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन विकास कार्यों में गुजरात जलापूर्ति और गटर व्यवस्था बोर्ड, सड़क एवं भवन विभाग (राज्य), नड़ियाद महानगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के अलावा कपड़वंज नगर पालिका और पशुपालन विभाग के कार्य शामिल हैं।

कार्यक्रम में जिला राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, विधायक सर्वश्री पंकजभाई देसाई, अर्जुनसिंह चौहान, राजेशकुमार झाला, कल्पेशभाई परमार, योगेन्द्रसिंह परमार, संगठन के पदाधिकारी श्री अजय ब्रह्मभट्ट और सुश्री नयनाबेन पटेल, जिला कलेक्टर श्री अमित प्रकाश यादव, नड़ियाद महानगर पालिका आयुक्त श्री जी.एच. सोलंकी, जिला विकास अधिकारी श्री जयंत किशोर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, अग्रणी और खेड़ा के नागरिक उपस्थित रहे।

# पश्चिम रेलवे द्वारा होली त्योहार के अवसर पर हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

### पश्चिम रेलवे से अब तक 231 हॉलिडे स्पेशल ट्रेन सेवाएँ अधिसूचित;सुदृढ़ होल्डिंग एवं भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाएं सुनिश्चित

**(जीएनएस)।** त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा एवं सुगम आवागमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान संभावित यात्री भीड़ को संभालने हेतु व्यापक तैयारियों के साथ पूरी तरह से सजग है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए अब तक 231 हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। ये स्पेशल ट्रेनें 01 मार्च से 22 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए परिचालित की जाएंगी, जिनमें उत्तर एवं पूर्व भारत के प्रमुख क्षेत्रों—उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित अन्य महत्वपूर्ण राज्य—पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों की योजना यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने तथा त्योहारों के दौरान आरामदायक एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अग्रिम योजना बनाकर तथा विभिन्न सेक्टरों में आरक्षण प्रवृत्तियों और यात्री मांग की निरंतर निगरानी करते हुए एक सक्रिय एवं यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे होली त्योहार के दौरान यात्री भीड़ के सुचारु प्रबंधन हेतु अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं एवं व्यापक यात्री सुविधा उपायों के साथ पूरी तरह तैयार है। बुकिंग पैटर्न एवं यात्री आवागमन की सतत निगरानी की जा रही है तथा जहाँ संभव हो नियमित ट्रेनों में कोचों की वृद्धि भी की जा रही है। यात्रियों की मांग के आधार पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों पर भी विचार किया जाएगा तथा आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जाएगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में सहायता हेतु विभिन्न मीडिया माध्यमों से स्पेशल ट्रेनों एवं यात्री सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री विनीत ने आगे बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर भारी यात्री भीड़ की संभावना को देखते हुए पश्चिम रेलवे के प्रमुख टर्मिनलों एवं आरंभिक स्टेशनों पर व्यापक तौर पर भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाएं पहले से ही लागू कर दी गई हैं। मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, उधना, सूरत, अहमदाबाद सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रवेश और बोर्डिंग को नियंत्रित करने हेतु समर्पित यात्री होल्डिंग क्षेत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इन होल्डिंग क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय ब्लॉक, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पंखे तथा जन-उद्घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कतार प्रबंधन, यात्री मार्गदर्शन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ, जीआरपी एवं वाणिज्यिक कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की योजना बनाई गई है। सीसीटीवी निगरानी चौबीसों घंटे की जा रही है तथा संवेदनशील स्टेशनों पर वरिष्ठ रेल अधिकारी तैनात रहेंगे, ताकि संचालन की निगरानी कर आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यात्रियों की सुगम आवाजाही एवं भीड़ से बचाव के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, मोबाइल टिकटिंग व्यवस्थाएं तथा सघन उद्घोषणाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ-साथ मजबूत स्टेशन-स्तरीय तैयारियां एवं समन्वित भीड़ प्रबंधन रणनीतियां, होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे की तत्परता को दर्शाती हैं।

पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से अपील करती है कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं, निर्धारित होल्डिंग क्षेत्रों का उपयोग करें तथा रेलवे स्टाफ एवं सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें, ताकि त्योहारों के दौरान सभी के लिए सुचारु आवागमन एवं सुखद यात्रा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

# शराबबंदी की धरती पर रईसी की रंगीन रात, साणंद में हाई-प्रोफाइल शराब-हुक्का महफिल का भंडाफोड़

**(जीएनएस)।** अहमदाबाद/साणंद। जिस गुजरात को देश में शराबबंदी के सबसे सख्त कानूनों वाला राज्य माना जाता है, वहीं एक बार फिर कानून को ठेंगा दिखाती रईसी और रंगीन रात का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने बुधवार देर रात साणंद क्षेत्र में छापा मारकर एक हाई-प्रोफाइल शराब और हुक्का पार्टी का पर्दाफाश किया, जिसमें महंगी विदेशी शराब, हुक्का, तेज म्यूजिक और लग्जरी गाड़ियों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 43 पुरुषों और 38 महिलाओं समेत कुल 81 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें शहर के जाने-माने बिल्डर, व्यापारी और डॉक्टर शामिल बताए जा रहे हैं। यह पूरी घटना अहमदाबाद ग्रामीण इलाके में साणंद-नलसरोवर रोड पर स्थित निर्वाणा ग्रीन्स वीकेंड होम की है। जानकारी के मुताबिक, यहां बुधवार रात एक निजी पार्टी का आयोजन किया गया था। बाहर पार्किंग में BMW और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की कतार लगी थी, जबकि अंदर मास्क लगाए महिलाएं और पुरुष तेज म्यूजिक पर नाचते नजर आ रहे थे। पार्टी में शामिल लोग यह मानकर निश्चिंत थे कि यह एक प्राइवेट आयोजन है और कानून की नजर से दूर रहेगा, लेकिन पुलिस की अचानक एंट्री ने पूरी महफिल में अफरा-तफरी मचा दी।




पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पार्टी आदर्श अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित की गई थी। इस मौके को 'सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन' के रूप में मनाने के लिए विदेशी और महंगी शराब की व्यवस्था की गई थी, साथ ही हुक्का भी खुलेआम परोसा जा रहा था। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर 11 टेबल पर केक, शराब की बोतलें, हुक्का और अन्य सामग्री सजी हुई थी। तेज म्यूजिक के बीच लोग मास्क पहनकर डांस कर रहे थे, ताकि पहचान छिपी रहे और माहौल पूरी तरह बेफिक्र बना रहे। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस के एसपी ओमप्रकाश जाट ने बताया कि उन्हें इस पार्टी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने देर रात छापा मारा। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग भागने की कोशिश में इधर-उधर दौड़ते नजर आए, लेकिन परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया था, जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में शराब, हुक्का का सामान और 20 से अधिक लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2.91 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें विदेशी शराब की बोतलें, हुक्का सेट, म्यूजिक सिस्टम और महंगी कारें शामिल हैं। जब्त की गई गाड़ियों में BMW, Audi और अन्य प्रीमियम ब्रांड्स की कारें बताई जा रही हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पार्टी में शामिल लोग समाज के संपन्न और प्रभावशाली वर्ग से थे।

छापेमारी के बाद सभी 81 लोगों को साणंद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों की मेडिकल जांच के साथ-साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई आरोपी 40 साल से कम उम्र के हैं और विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। साणंद, जो अहमदाबाद जिले का एक तेजी से विकसित होता कस्बा है, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर, औद्योगिक इकाइयां और हाईराइज रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। ऐसे इलाके में इस तरह की शराब और हुक्का पार्टी का पकड़ा जाना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध गतिविधियां किस तरह गुपचुप तरीके से फल-फूल रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर गुजरात में शराबबंदी की प्रभावशीलता पर बहस को तेज कर दिया है। एक ओर सरकार सख्त कानूनों और कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की हाई-प्रोफाइल पार्टियां यह सवाल उठाती हैं कि क्या कानून का डर केवल आम लोगों तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई, किस नेटवर्क के जरिए इसकी सप्लाई हुई और क्या इससे पहले भी इस तरह की पार्टियां आयोजित की जाती रही हैं।

# मदार-पालनपुर सेक्शन में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

**(जीएनएस)।** उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल के मदार-पालनपुर रेलखण्ड पर मावल-श्री अमीरगढ़ स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 812 पर स्टील गर्डर रिप्लेसमेंट कार्य हेतु ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है

**आंशिक रद्द ट्रेनें**

▸▸ 7 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस साबरमती-आबूरोड के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

▸▸ 6 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आबूरोड-साबरमती के बीच आंशिक रद्द रहेगी।

रिशेड्यूल ट्रेनें

1. 6 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 12462 साबरमती-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस साबरमती से अपने निर्धारित समय से 01 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।
2. 6 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 22548 साबरमती-ग्वालियर एक्सप्रेस साबरमती से अपने निर्धारित समय से 01 घंटे की देरी से प्रस्थान करेंगी।
3. 5 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस अरावली एक्सप्रेस श्रीगंगानगर से अपने निर्धारित समय से 03 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।
4. 6 फरवरी 2026 की ट्रेन संख्या 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेंट्रल स्पेशल भगत की कोठी से अपने निर्धारित समय से 03.30 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

# यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल की विभिन्न ट्रेनों में स्थाई रूप से अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा

**(जीएनएस)।** यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ प्रमुख ट्रेनों में स्थाई रूप से अतिरिक्त जनरल कोच लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे दैनिक यात्रियों एवं सामान्य श्रेणी के यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अतिरिक्त कोच का विवरण निम्नानुसार हैः—

ट्रेन संख्या 20966/20965 भावनगर–साबरमती–भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में स्थाई रूप से 04 जनरल कोच लगाए जाएंगे। यह सुविधा 06 फरवरी, 2026 से भावनगर एवं गांधीग्राम दोनों स्टेशनों से प्रभावी होगी।

ट्रेन संख्या 12905/12906 पोरबंदर–शालीमार–पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में स्थाई रूप से 01 अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जा रहा है। यह कोच 04 फरवरी, 2026 से पोरबंदर स्टेशन से तथा 06 फरवरी, 2026 से शालीमार स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इसके पश्चात इस ट्रेन में जनरल कोचों की संख्या 02 से बढ़कर 03 हो जाएगी।

ट्रेन संख्या 20968/20967 पोरबंदर–सिकंदराबाद–पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी स्थाई रूप से 01 अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा 03 फरवरी, 2026 से पोरबंदर स्टेशन से तथा 04 फरवरी, 2026 से सिकंदराबाद स्टेशन से लागू हो चुकी है। इसके साथ ही इस ट्रेन में जनरल कोचों की संख्या 02 से बढ़कर 03 हो गई है।

रेल प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित एवं आरामदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

ट्रेन के ठहराव, संरचना एवं समय-सारणी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

# कर्मयोगियों के स्वाभिमान को समर्पित सेवा का नया अध्याय, सूरत में 'खेमानी भोजन सेवा' का गरिमामय आरंभ

**(जीएनएस)।** सूरत। समाज की नींव को मजबूत करने वाले कर्मयोगियों के सम्मान, स्वास्थ्य और स्वाभिमान को केंद्र में रखते हुए सूरत में एक अनुकरणीय पहल की शुरुआत हुई है। खेमानी वेलफेयर फाउंडेशन एवं सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित 'खेमानी भोजन सेवा' का गुरुवार को गरिमामय वातावरण में शुभारंभ किया गया। यह सेवा केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मसम्मान, संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखा गया है। पहल की सबसे खास बात यह है कि यहां भोजन को दया का विषय न बनाकर सम्मान से जोड़ा गया है। इसी भावना के तहत भोजन पूरी तरह निःशुल्क न रखकर कर्मयोगियों के लिए मात्र 10 रुपये का स्वाभिमान शुल्क तय किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें भरपेट, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

'खेमानी भोजन सेवा' का नियमित संचालन सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक किया जाएगा। यह सेवा मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के सामने, फोस्टा ऑफिस के पास संचालित होगी, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और कर्मयोगी प्रतिदिन कार्य के लिए आते-जाते हैं। आयोजकों का मानना है कि इसी क्षेत्र में सेवा की शुरुआत करने से अधिक से अधिक जरूरतमंद कर्मयोगियों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा।

# विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में गुजरात शीर्ष तीन राज्यों में शामिल

**(जीएनएस)।** गांधीनगर : भारत के पर्यटन क्षेत्र में 2024 में मजबूत विकास देखा गया है, जिसमें देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों (एफटीए) की संख्या 99.5 लाख पर पहुंच गई है। उधर, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) भी बढ़कर 2.05 करोड़ हो गया है, जो कोविड से पहले के वर्ष 2019 की तुलना में 14.85 फीसदी की वृद्धि दिखाता है। राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज इस वृद्धि में गुजरात भी विदेशी पर्यटकों के लिए तीसरे सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है, जो वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन क्षेत्र की इस प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने गुजरात की संस्कृति, अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्यों और आधुनिक आकर्षणों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उनके अविरत प्रयासों के कारण गुजरात आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र बन गया है और भारत के पर्यटन क्षेत्र के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार



**▸▸ मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, सोमनाथ, द्वारका, गिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कच्छ रण उत्सव देखने पहुंचे विदेशी पर्यटक**

2024 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से शीर्ष पांच राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का समावेश होता है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2024 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत पूरी दुनिया में 20वें स्थान पर रहा, जहां 2.05 करोड़ पर्यटक भारत आए। वहीं, 2023-24 में पर्यटन क्षेत्र में 8.46 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर) और स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजनाओं के सहयोग से इस सफलता को प्राप्त करने में मदद मिली है।

गुजरात ने इन पहलों के सहयोग के साथ राज्य के धार्मिक स्थलों, इको-टूरिज्म, सांस्कृतिक विरासत और आइकॉनिक स्थलों को बढ़ावा देने का अहम कार्य किया है। गुजरात की यह सफलता राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों ने पर्यटन क्षेत्र में श्रेष्ठता के नए मानक स्थापित किए हैं और पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध बनाकर वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया है।

विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर रहे गुजरात की उपलब्धि केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट विजन, सशक्त नेतृत्व और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है। हेरिटेज, इको-टूरिज्म और आइकॉनिक स्थलों पर ध्यान केंद्रित करके गुजरात एक पसंदीदा वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2024 में गुजरात आए विदेशी पर्यटक राज्य के विविधतापूर्ण स्थलों को देखने पहुंचे, जिनमें धार्मिक क्षेत्र, हेरिटेज स्थल, वन्यजीव और आधुनिक विकास के आकर्षण शामिल हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में हर साल बड़ी संख्या में दुनिया भर के श्रद्धालु-पर्यटक आते हैं, जबकि आध्यात्मिक साधकों के लिए द्वारका हमेशा से पसंदीदा स्थल रहा है। एशियाई शेरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात आने वाले पर्यटकों के लिए हमेशा से पसंदीदा स्थल रहा है। केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता और आधुनिक इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक बनकर खड़ी है। इन स्थानों पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कच्छ के सफेद रण ने सैलानियों के लिए एक अनोखे परिदृश्य और सांस्कृतिक अनुभव के द्वार खोल दिए हैं। इन स्थलों के आकर्षण के कारण वर्ष 2024 में विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या के मामले में गुजरात ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

# पश्चिम से पूरब तक पैडल पर राष्ट्रप्रेम: आशा मालवीय की सोलो साइकिल यात्रा बनी नारी शक्ति और संकल्प की जीवंत मिसाल

**(जीएनएस)।** वडोदरा की सड़कों से होकर इन दिनों एक ऐसी कहानी गुजर रही है, जो केवल किसी खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। नेशनल लेवल की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही आशा मालवीय की सोलो साइकिलिंग यात्रा भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रप्रेम और अटूट इच्छाशक्ति का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। यह यात्रा 78वें इंडियन आर्मी डे से मिली प्रेरणा का परिणाम है, जिसने आशा मालवीय को एक बार फिर देश की सड़कों पर उतरने और अपने पैडल के जरिए समाज से संवाद करने का संकल्प दिया। वर्तमान में आशा मालवीय वडोदरा में हैं और यहां उनका स्वागत केवल एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत के रूप में किया जा रहा है। वडोदरा पहुंचने पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर से मुलाकात की और शहर के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों से संवाद किया। बच्चों और युवाओं के साथ उनकी बातचीत ने यह साफ कर दिया कि यह यात्रा सिर्फ दूरी तय करने का अभियान नहीं है, बल्कि सोच बदलने और आत्मविश्वास जगाने की मुहिम है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। यह साइकिल यात्रा राजस्थान के जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड मुख्यालय से शुरू हुई थी। वहां से निकलकर आशा मालवीय अब तक करीब 7,800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों,




शहरों और कस्बों से गुजरते हुए उनकी यात्रा लोगों के बीच उत्सुकता और सम्मान का विषय बन गई है। कहीं लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, तो कहीं महिलाएं और बच्चियां उन्हें देखकर अपने सपनों को नई उड़ान देते हुए महसूस करती हैं। यह यात्रा सड़कों पर चलती हुई एक चलती-फिरती प्रेरणादायी कथा बन गई है।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नटराम गांव की रहने वाली आशा मालवीय का जीवन संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है। एक साधारण ग्रामीण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। सीमित संसाधन, सामाजिक चुनौतियां और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनकी मां ने हर कदम पर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया और परिवार ने त्याग करके उनके लक्ष्य को मजबूत आधार दिया। आज वही बेटी पूरे देश में नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी है।

आशा मालवीय इससे पहले भी कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायी अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। उन्होंने 28 राज्यों में 26,000 किलोमीटर की नेशनल वुमन एम्पावरमेंट साइकिलिंग कैंपेन पूरी की, जिसने देशभर की महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश पहुंचाया। इसके अलावा 17,500 किलोमीटर का "मजबूत सेना, खुशहाल भारत" मिशन उनके राष्ट्रप्रेम और सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक रहा। इस मिशन के दौरान उन्होंने कारगिल, सियाचिन, उमलिंग ला पास और रेजांग ला मेमोरियल जैसे दुर्गम और जोखिम भरे क्षेत्रों में साइकिलिंग कर अद्भुत साहस का परिचय दिया।

इन अभियानों के दौरान आशा मालवीय ने यह साबित किया कि देशभक्ति केवल शब्दों या मंचों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे कर्म और समर्पण के जरिए भी जिया जा सकता है। बर्फ से ढके पहाड़, पतली सड़कें, तेज हवाएं और कम ऑक्सीजन जैसे हालात उनके हौसले को डिगा नहीं सके। हर कठिनाई के सामने उन्होंने खुद को और मजबूत पाया। उनका यह सफर उन तमाम युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं।

साइकिलिंग के साथ-साथ आशा मालवीय ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 20,500 फीट ऊंची बीसी रॉय पीक और 19,545 फीट ऊंची तेनजिंग खान पीक पर सफल चढ़ाई कर यह दिखाया कि मजबूत इरादों के आगे ऊंचाइयां भी झुक जाती हैं। पर्वतारोहण के दौरान उन्होंने न केवल शारीरिक क्षमता, बल्कि मानसिक दृढ़ता और धैर्य का भी परिचय दिया। यह उपलब्धियां उनके व्यक्तित्व को और भी प्रेरणादायी बनाती हैं।